भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 535

23.07.2026 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में वनीकरण

535 **श्री संजय सेठः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हरित भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने हेक्टेयर क्षरित वन भूमि का सफलतापूर्वक पुनरुद्धारित किया गया है;

(ख) क्या 'नगर वन' (शहरी वन) के तीव्र विकास से उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में हरित आवरण और वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(ग) वर्ष 2025-26 के दौरान इन वनीकरण अभियानों के लिए राज्य को सक्रिय रूप से संवितरित की गई और राज्य द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) नवरोपित पौधों के सतत रखरखाव और संरक्षण में स्थानीय समुदायों तथा स्वयं सहायता समूहों की सफल भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन वृक्षारोपणों की उत्तरजीविता दर की सटीक निगरानी के लिए भू-अंकन (जियो-टैगिंग) और ड्रोन निगरानी को एकीकृत करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में, राष्ट्रीय हरित मिशन (जीआईएम) के तहत कार्यकलापों का कार्यान्वयन वर्ष 2023-24 में शुरू हुआ और अब तक पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना के अन्तर्गत 4,202.25 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जा चुका है।

(ख) मंत्रालय नगर वन योजना (एनवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2026-27 की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिकाएं विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में नगरवासियों की

जीवन गुणवत्ता में सुधार के अलावा वनों से बाहर वृक्षों और हरित आवरण, जैव विविधता में बढ़ोतरी और पारिस्थितिकीय लाभों में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय मुख्य रूप से बाड़ लगाने, मिट्टी की नमी संरक्षण उपायों और संबंधित कार्यकलापों, प्रशासनिक कार्यकलापों, वृक्षारोपण तथा रखरखाव की लागत को कवर करने के लिए कैम्पा के राष्ट्रीय प्राधिकरण से राशि जारी करता है। इस बात का आकलन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है कि नगर वनों के तीव्र विकास से हरित आवरण और वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब तक, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 39 नगर वन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(ग)और(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वनीकरण और पारिस्थितिकी बहाली कार्यकलापों के लिए राज्य को ₹ 9.81 करोड़ की कुल राशि जारी की गई, जिसमें ₹ 3.30 करोड़ रुपये राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के तहत और ₹ 6.51 करोड़ रुपये नगर वन योजना के तहत सम्मिलित हैं। जीआईएम के तहत जारी राशि में से, राज्य ने ₹ 3.30 करोड़ के उपयोग की सूचना दी है। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) जैसे संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिसमें स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये समितियां वनीकरण और पारिस्थितिकी बहाली कार्यकलापों की योजना, कार्यान्वयन, संरक्षण, रखरखाव और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे पारिस्थितिक बहाली, जैव विविधता संरक्षण और वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

(ङ) वृक्षारोपण की निगरानी एक बहु-स्तरीय पद्धति का पालन करती है जिसमें केंद्रीय और राज्य तंत्र दोनों शामिल हैं। राज्य वन विभाग वार्षिक भौतिक सत्यापन और अन्य पक्ष की निगरानी करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जियो-टैग किए गए चित्रों और केएमएल फाइलों के माध्यम से निगरानी शामिल है। पौध के जीवित रहने की दर के आकलन के आधार पर सुधार के उपाय किए जाते हैं, जिनमें खाली जगहों को भरना और रखरखाव शामिल है। मंत्रालय निगरानी सटीकता बढ़ाने के लिए जियो-टैगिंग और रिमोट सेंसिंग सहित प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरणों के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) वन आवरण और संसाधनों का समय-समय पर आकलन करता है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए वृक्षारोपण की जियो-टैगिंग भी पूरी हो चुकी है।

******